

आरबीआई ने अपना आखिरी मौका हासिल किया

साभार : लाइव मिंट

03 अगस्त, 2017

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3 (भारतीय अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

क्यों किया

1. इस नीति तक पहुँच के लिए जिस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक दर में कटौती पर एकतरफा दांव बनाया था, वह काफी दिलचस्प था। देखा जाए तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की मुद्रास्फीति मार्च में 3.9% से मई में 2.2% तक पहुंच गई और विशेष रूप जून में 1.5% तक पहुंच गई थी, जो कि RBI के सबसे निचले स्तर के अनुमान 2-3.5% से भी कम थी।
2. इसके अलावा, बाजार की उम्मीदें इस तथ्य से बढ़ी है कि कोर मुद्रास्फीति, जो खाद्य और ईंधन की कीमतों को शामिल नहीं करती है, 4% के महत्वपूर्ण अवरोध को तोड़ते हुए, जून में 3.8% पर आ गयी।
3. आरबीआई हमेशा कोर मुद्रास्फीति में लगातार 4% से ऊपर ही स्थित रहा है जो इसके आत्मविश्वास को अवरुद्ध करता है और बताता है कि सीपीआई मुद्रास्फीति 4% स्तर पर कायम रखा जायेगा, जो आरबीआई का लक्ष्य भी है।

REPO RATE LOWERED BY 25 BPS TO 6%	WHAT'S NEW FROM RBI	WHAT'S IN IT FOR US
	INFLATION PROJECTION LOWERED MARGINALLY TO ABOVE 4%, FROM TOP END OF THE BAND OF 4.5%	MCLR system of pricing loans to give way to a new benchmark

कारण-

इस नीति में भारतीय रिजर्व बैंक को कटौती के लिए प्रेरित किए जाने वाले कारक-

1. मुद्रास्फीति से संबंधित जोखिमों में कमी आना।
2. मानसून बारिश अनुकूल हैं।
3. दाल बुवाई के शुरुआती भय में कमी आना।
4. अंतर्राष्ट्रीय वस्तु की कीमतें स्थिर हैं।

भविष्य की चुनौती-

1. इसके अलावा, आरबीआई इस तथ्य से अवगत है कि बेस इफेक्ट लुप्त हो जाने से, मुद्रास्फीति का उच्च होने की संभावना बढ़ जाती है।
2. इस बात को लेकर चिंता यह है कि राज्यों द्वारा कृषि ऋण छूट के परिणामस्वरूप राजकोषीय गिरावट आ सकती है और भविष्य में मुद्रास्फीति के दबाव का कारण बन सकती है।
3. मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, क्योंकि राज्य जल्द ही केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ अपनी वेतन वृद्धि को लागू कर सकते हैं।
4. आरबीआई के अनुमान के मुताबिक इससे मुद्रास्फीति में 100 आधार अंक जुड़ जाने की संभावना बढ़ जाती है।
5. वैश्विक तरलता के कम होने की पूरी संभावना है, जैसाकि फेड और यूरोपीय सेंट्रल बैंक अपनी बैलेंस शीट को कम करने की बात कर रहे हैं।
6. बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) की सीमाओं में संभावित वृद्धि के साथ, तरलता को भी शामिल करने की संभावना है और भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार संचालन (ओएमओ) के माध्यम से तरलता को सिक्वोरिटीज की बिक्री से बाहर निकलना जारी रखता है।

क्या रेट कट सफल होगा-

1. हम ऐसा नहीं सोचते हैं और बैंकिंग क्षेत्र से वास्तविक क्षेत्र तक उधार देने में नाटकीय रूप से सुधार करने की संभावना नहीं है।
2. डर इस बात का भी है कि इस नवीनतम दर में कटौती, धन-आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) की सीमांत लागत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं ला सकती है।
3. इस प्रकार, मौद्रिक नीति के संचरण का मुद्दा रिजर्व बैंक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र जिससे उसे निपटना है।

मौद्रिक नीति

इस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है, उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। इसका उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना होता है। इसका उद्देश्य कम और स्थिर मुद्रास्फीति तथा विकास को बढ़ावा देने जैसे विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करना है। मौद्रिक नीति ही यह तय करती है कि रिजर्व बैंक किस दर पर बैंकों को कर्ज देगा और किस दर पर उन बैंकों से वापस पैसा लेगा।

प्रक्रिया

- रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) मौद्रिक नीति निर्माण में गवर्नर की सहायता करता है। अर्थव्यवस्था के सभी शेर धारकों के विचारों, तकनीकी परामर्शदात्री समिति (टीएसी) की सलाह और रिजर्व बैंक का विश्लेषणात्मक कार्य नीति रेपो दर पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान करता है।
- वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी) मुख्य रूप से दैनिक चलनिधि प्रबंध परिचालनों के माध्यम से मौद्रिक नीति को कार्यान्वित करता है।
- वित्तीय बाजार समिति (एफएमसी) नीति दर, मुद्रा बाजार दरों और चलनिधि परिस्थितियों के बीच अनुरूपता की समीक्षा करने के लिए दैनिक आधार पर बैठक करता है।

लक्ष्य: • कम और स्थिर मुद्रास्फीति, • वित्तीय स्थिरता और
• समावेशी विकास हासिल करना

पारदर्शिता:

मौद्रिक नीति में आघातों के बारे में अनुचित डर से बचने के लिए प्रभावी संप्रेषण पर जोर दिया जाता है। पारदर्शिता से मौद्रिक नीति की प्रभाव क्षमता बढ़ती है। रिजर्व बैंक अपने मौद्रिक नीति रूझान में इसके तर्क का पारदर्शी तरीके से वर्णन करता है। नीति निर्माण में परामर्शदात्री दृष्टिकोण पर जोर देता है और नीति परिचालन में स्वायत्तता रखता है। इसके अलावा, यह लक्ष्यों को समष्टि आर्थिक नीतियों के अन्य तत्वों के साथ मिला कर कार्य करता है।

मौद्रिक नीति समिति

- यह समिति खुदरा मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत (2 प्रतिशत कम या ज्यादा) के लक्षित स्तर पर रखने के उद्देश्य से मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है।
- रिजर्व बैंक द्वारा नामित सदस्यों में गवर्नर, डिप्टी गवर्नर तथा केंद्रीय बैंक के एक और सदस्य है।
- इसमें नीतिगत दर के बारे में निर्णय समिति करती है, जबकि इससे पहले इस संदर्भ में फैसला रिजर्व बैंक के गवर्नर किया करते थे।
- वित्त अधिनियम 2016 के जरिये भारतीय रिजर्व बैंक कानून, 1934 में संशोधन करने के बाद एमपीसी का गठन किया गया है।
- यह समिति 27 जून, 2016 से प्रभावी है।
- एमपीसी सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति के लक्ष्य और उसे हासिल करने को ध्यान में रखकर नीतिगत दर स्थापित करने के बारे में फैसला करेगी।

- सरकार के साथ हुए समझौते के तहत रिजर्व बैंक खुदरा मुद्रास्फीति दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ 4 प्रतिशत पर बनाए रखने को प्रतिबद्ध है।
- एमपीसी नियमों के तहत प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा और अगर मामला बराबरी पर आता है तो रिजर्व बैंक के गवर्नर निर्णायक वोट देंगे।
- समिति के सदस्यों की नियुक्ति चार साल के लिए होगी और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

केंद्रीय सरकार द्वारा चुने गए समिति के सदस्य

- चेतन घाटे-** उस पांच सदस्यीय तकनीकी परामर्श समिति में शामिल रहे हैं जो प्रत्येक मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले रिजर्व बैंक को नीतिगत दरों के बारे में परामर्श देती रही है। मौद्रिक नीति का इनकी विशेषज्ञता मैक्रोइकोनॉमी, विकास, मौद्रिक-राजकोषीय नीति और पॉलिटिकल इकोनॉमी में है। 2014 में इन्हें इकोनॉमिक्स रिसर्चर का अवार्ड मिला था।
- पम्मी दुआ-** मैक्रोइकोनॉमी में देश के प्रतिष्ठित प्रोफेसरों में शामिल हैं। बिजनेस साइकिल एनालिसिस, टाइम सीरीज इकोनोमेट्रिक्स फोरकास्टिंग इनके प्रमुख विषय हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर की चेयरपर्सन भी हैं। इनकी लिखी पुस्तकें हैं-बैंचमार्किंग फॉर परफॉर्मेंस इवेलुएशन, फोरकास्टिंग इंडियन मैक्रोइकोनॉमिक वैरिएबल्स डिटरमिनेसन ऑफ यील्ड्स ऑन गवर्मेंट सिक्कुरिटीज इन इंडिया।
- रवीन्द्र एच. ढोलकिया-** केंद्र और राज्य सरकारों के लिए नीतियाँ बनाने वाली कई टीमों का हिस्सा रहे। डाक नेटवर्क ठीक करने, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय, सरकारी खर्च के प्रबंधन और बचत निवेश पर बनी समितियों के सदस्य रहे। विश्व बैंक और यूनिसेफ सहित कई सरकारी-निजी कंपनियों के सलाहकार रहे।

क्यों पड़ी मौद्रिक नीति समिति की आवश्यकता

- ब्याज दरों को लेकर अक्सर सरकार और रिजर्व बैंक के गवर्नर के बीच टकराव जैसे हालात का रहना।
- सरकार का जोर विकास पर रहा और रिजर्व बैंक का महंगाई को कम रखने पर। इसलिए बैंक हमेशा मौद्रिक नीति अपने हिसाब से बनाता रहा।
- अक्टूबर, 2012 में तत्कालीन गवर्नर डी सुब्बाराव और यूपीए सरकार में वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बीच टकराव इस हद तक बढ़ गया था कि चिदंबरम ने कह दिया कि विकास भी महंगाई जितनी ही बड़ी चुनौती है और अगर सरकार को इस चुनौती से निपटने के रास्ते पर अकेले चलना है तो वह अकेले ही चलेगी।
- टकराव की इसी पृष्ठभूमि में एमपीसी का गठन हुआ था।

अन्य संबंधित तथ्य

- 23 जनवरी, 2017 को पूर्व राजस्व एवं व्यय सचिव और सांसद एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाली राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली को सौंपी।
- राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत।
- राजस्व घाटा 0.8 प्रतिशत।
- केन्द्र-राज्य का संयुक्त कर्ज सीमा 60 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।
- अगर केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ये सिफारिशों और ऋण प्रबंधन और राजकोषीय दायित्व विधेयक के मसौदे की अन्य सिफारिशों स्वीकार कर लेती हैं तो यह मौजूदा एफआरबीएम ऐक्ट की जगह ले लेगा।

संभावित प्रश्न

“राज्यों द्वारा कृषि ऋण छूट से राजकोषीय गिरावट आ सकती है, जो मुद्रास्फीति के दबाव का कारण बनती है”

आप इस कथन से कहा तक सहमत हैं? स्पष्ट करें।

(200 शब्द)